



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128658

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19105 वर्ष 2026

फरहान अहमद

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता	:	गुंजन शर्मा
प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता	:	शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान जमानत आवेदन मामला अपराध संख्या 15 वर्ष 2026, अंतर्गत धारा 87, 137(2) भारतीय न्याय संहिता, पुलिस स्टेशन हथगांव, जिला फतेहपुर में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि आवेदक निर्दोष है और उसे प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। पीड़िता पिछले एक साल से आवेदक से प्रेम करती थी। उसकी शादी किसी और लड़के से तय हो गई थी, इसलिए वह 2.1.2026 को अपना घर छोड़कर आवेदक के साथ रहने चली गई। पीड़िता ने आवेदक को बुलाया और वे इलाहाबाद गए और एक किराए के मकान में ठहरे। अगले दिन वे आगरा गए और वहां 15 दिन तक रहे। पीड़िता का कहना है कि

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसने अपनी इच्छा से घर छोड़ा था और आवेदक उसे बहला-फुसलाकर नहीं ले गया था। पीड़िता की उम्र लगभग 17 वर्ष थी और उसने कहा कि वह आवेदक से शादी करेगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 183 के अंतर्गत दर्ज अपने अभिकथन में उसने कहा कि वह 2.1.2026 को देहरादून गई थी, लेकिन 3.1.2026 को अपने घर लौट आई और उसके साथ कोई दुर्यवहार नहीं हुआ था। आगे यह निवेदन किया गया है कि पीड़िता अपनी सहमति से इस घटना में शामिल प्रतीत होती है और उसके अभिकथन के अवलोकन से आवेदक के विरुद्ध कोई अपराध सिद्ध नहीं होता है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि आवेदक 5.2.2026 से जेल में दिन काट रहा है और यदि, उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और परीक्षण में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और यह तर्क दिया है कि आवेदक के विरुद्ध अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य हैं, इसलिए, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

5. मैंने पक्षों की ओर से प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी दलीलों, आरोपों की प्रकृति, अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों, आवेदक द्वारा भुगती गई कारावास की अवधि, किसी भी आपराधिक पूर्ववृत्त के अभाव पर विचार करने के बाद, और मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय पाता है कि आवेदक ने जमानत दिए जाने के लिए मामला सिद्ध कर दिया है।

7. तदनुसार, जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. उपरोक्त मामले अपराध में संलिप्त आवेदक- **फरहान अहमद** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप उसके व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानती, प्रत्येक समान राशि के प्रस्तुत

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतियों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह वचनबंध देना होगा कि जब साक्षीगण न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, परीक्षण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित करेगा।

(ii) आवेदक को प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दंड संहिता/ 269 भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत कार्यवाही कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक परीक्षण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दंड प्रक्रिया संहिता/ 84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध, कानून के अनुसार अंतर्गत धारा 174-ए भारतीय दंड संहिता/ 209 भारतीय न्याय संहिता की कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक को (i) वाद आरम्भ करने, (ii) आरोप तय करने और (iii) धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता/ 351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अभिकथन दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित रहना होगा। यदि परीक्षण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो परीक्षण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का यह एक आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में किए गए संप्रेक्षण किसी भी तरह से विद्वान परीक्षण न्यायाधीश को साक्षियों के परिसाक्ष्य के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेगा।

(माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

23 जून, 2026

ललित शुक्ला

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।